सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-273
05/06/2018

कृषकों की सहायता के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है :– मुख्यमंत्री

पटना, 05 जून 2018 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज जहानाबाद जिला स्थित सुगांव में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री स्व0 सुखदेव प्रसाद वर्मा जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर बेहद खुशी हो रही है। आज प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री स्व0 सुखदेव प्रसाद वर्मा जी के मूर्ति के अनावरण का मुझे मौका मिला है। सुखदेव वर्मा जी को गया जिला सहित बिहार के सभी जगहों पर अपने समय में लोग उन्हें जानते थे, वे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी थे। दो बार विधायक, सांसद और मंत्री भी रहे। उन्होंने बड़ी ही लगन से लोगों की सेवा की। उन्होंने राजनीति को सेवा का मार्ग समझा। राजनीति करने वाले लोगों को यह समझने की जरुरत है कि राजनीति में लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा का भाव लेकर काम करना चाहिए। इसी मगध की धरती से चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को कहा था कि राजनीति सेवा की चीज है। राजा बने हो तो सुख के लिए मत सोचो, कष्ट झेलना पड़ेगा, लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति के आज के दौर में गिरावट आयी है। अभी जो पुस्तिका का विमोचन हुआ है, उसमें सुखदेव वर्मा जी के बारे में पढ़कर यह जानकारी मिली कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस वक्त उनके खाते में मात्र 700 रुपए था। उनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किया गया था। वे ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो अपने परिवार के लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ गए थे। वह आज के लिए एक आदर्श हैं। अगर पैसा नहीं रहे और आप जनता के बीच में लोकप्रिय हैं तो भविष्य के लिए कोई बेहतर रास्ता निकल ही जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जिस जगह पर उपस्थित हुए हैं, वो सुगांव हैं यानि एक अच्छा सा गांव और जिनकी आज मूर्ति का अनावरण हुआ है उनका नाम सुखदेव था यानि सबको सुख देने वाले। उन्हीं के पुत्र श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा जी बिहार सरकार में शिक्षा एवं विधि मंत्री हैं। मुझे उम्मीद है अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए जिम्मेवारियों को बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग विकास के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य हो, समाज कल्याण का क्षेत्र हो, बुनियादी ढांचे का निर्माण हो, पुल–पुलिये का निर्माण हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। जब हम सत्ता संभाले थे उस समय, सर्वे कराया गया तो यह पता चला कि साढ़े बारह प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मुझे याद है कि जब मैं सांसद था उस समय अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक 10 वर्षीय बालक ने मुझसे आकर कहा कि सर हमलोग पढ़ेंगे नहीं। मैंने उससे पूछा कि यहां स्कूल नहीं है, मास्टर नहीं हैं, उस पर वो चुप रहा। आज तक हम इस बात को नहीं भूले हैं। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए हमने सरकार में आते ही कई कदम उठाए। 27,000 स्कूल बनाए गए। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति

की गई। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए तालिमी मरकज और दलित बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए टोला सेवकों की बहाली की गई। अब 1 प्रतिशत से भी कम बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मुझे लोगों की सेवा करने की जिम्मेवारी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां जो मूर्ति लगी है उनके पुण्यतिथि पर हर वर्ष यहां राजकीय समारोह का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी वाली उमस देखकर मुझे वर्षा के लिए संदेह लग रहा है लेकिन मेरी प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो। हमलोग बाढ़ और सुखाड़ दोनों से परेशान रहते हैं। हमलोग बाढ़ पीड़ितों के लिए चिंतित रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित के लिए हमलोगों ने अनेक काम किए हैं। कृषि रोड मैप बनाकर उसे लागू किया गया। सात निश्चय योजना के तहत इस साल के अंत तक हर घर तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। हमलोगों की बिजली की योजना की प्रशंसा केंद्र सरकार ने भी की है और उसे हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य को लागू किया है। कल ही कैबिनेट की बैठक में हमलोगों ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय योजना के तहत फसल बीमा योजना लागू थी, जिसके अंतर्गत बीमा कंपनियों को बराबर राशि केंद्र और राज्य सरकार प्रीमियम के रुप में देती थी और 02 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को भी देना पड़ता था। फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को उतना भी नहीं मिल पाता है, जितना बीमा कंपनियों को राज्य एवं केंद्र सरकार से प्रीमियम के रुप में मिलता है। खरीफ और रबी फसलों के लिए बीमा कंपनियों को 400–400 करोड़ रुपये प्रीमियम के रुप में केंद्र एवं राज्य सरकार देती है और किसानों को सिर्फ 150 करोड़ का ही लाभ मिल पाता है। अतः फसलों के नष्ट होने, कम ऊपज होने पर कृषकों की सहायता करने के लिए राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना के समानांतर बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू करने का निर्णय किया है। इसके तहत किसानों को होने वाले नुकसान का आकलन कर उसके अनुसार सहायता दी जाएगी। इसके बारे में विज्ञापन एवं जिला प्रशासन के द्वारा भी लोगों की पूरी जानकारी दी जाएगी। जो रैयती किसान हैं और गैर रैयती हैं सबको इसका लाभ मिलका है। गैर रैयती लोगों के लिए किसान सलाहकार एवं वार्ड मेंबर के द्वारा रिपोर्ट तैयार कराया जाएगा। इसी साल के खरीफ फसल से ही यह योजना लागू हो जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। इस योजना के साथ–साथ आपदा के समय जो फसल की क्षति होती है, किसानों को अगले फसल के लिए जो सहायता दी जाती है, वो भी जारी रहेगी। हमलोग जितना संभव है किसानों की सहायता करते रहेंगे। हम समाज के न्याय के हर तबके के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। न्याय के साथ विकास का काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहानाबाद जिला की 5–6 महिलाओं ने 09 जुलाई 2015 को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में शराबबंदी की मांग की थी। आपलोगों की मांग पर हमने 05 अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। राज्य में कुछ धंधेबाज गड़बड़ करने वाले लोग हैं, उसके लिए आई0जी0 मद्य निषेध का गठन किया गया है। बिजली के खंभों पर अंकित एक फोन नंबर जिस पर आप तत्काल सूचना दीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और गड़बड़ी करने वालों पर उचित कार्रवाई होगी। शराबबंदी के बाद लोगों के परिवार की हालत बेहतर हुई है। गरीब गुरबों के कमाई का गाढ़ा हिस्सा शराब में खर्च हो जाता था। अब उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है। सर्वेक्षण से पता चला है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा, कपड़ा, फर्निचर, दूध, मिठाई आदि चीजों पर खर्च कर रहे हैं। आज कल कुछ लोग भ्रमित करने के लिए यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि शरबाबंदी कानून के तहत जेल जाने वाले ज्यादातर

लोग गरीब वर्ग से आते हैं। सही आंकड़ों का पता करने की जरूरत है। गड़बड़ करने वाले कोई भी हों, वे जेल जाएंगे। शराबबंदी से राज्य के लोग प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिया जिले के एक गांव में शराब कार्य में जो अनुसूचित जनजाति के लोग लगे हुए थे, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार के रुप में दुधारु पशु उपलब्ध कराया गया, जिससे वो दूध बेचने तथा पशु पालन का कार्य कर रहे हैं। हमलोग राज्य भर में ऐसे परिवारों का सर्वेक्षण करवा रहे हैं और उनके लिए 5–6 तरह के रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। चाहे कोई पशुपालन करना चाहता हो, ई–रिक्शा चलाना चाहता हो, दुकान खोलना चाहता हो। इसके लिए हरेक 40 लोगों पर एक आदमी नियुक्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार काम कर रही है। राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी आयी है लेकिन लड़कों की तुलना में लड़कियों का शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। लड़के और लड़की दोनों पर बराबर ध्यान देने की जरुरत है। राज्य सरकार लड़की के जन्म लेने पर तत्काल उसके माता–पिता को 2000 रुपये उपलब्ध करायेगी। एक साल के बाद आधार कार्ड से जोड़ने पर 1000 रुपये और अगले साल पूर्ण टीकाकरण कराने पर 2000 रुपये उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली एवं दूसरी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की पोशाक राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी गई है, तीसरी से पांचवी क्लास की लड़कियों की पोशाक राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए कर दी गई है, छठी से आठवीं क्लास तक की लड़कियों के लिए पोशाक राशि 700 से 1000 रुपए कर दी गई है, नौवीं से लेकर बारहवीं क्लास तक की लड़कियों के लिए पोशाक राशि 1000 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये कर दी गई है। बारहवीं पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 10,000 रुपये दिया जाएगा एवं विवाहित हो या अविवाहित बी0ए0 पास करने वाली लड़कियों को 25,000 रुपए दिया जाएगा। सातवीं से 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के सेनेटरी नैपकिन की राशि 150 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लड़कियों के जन्म लेने से लेकर ग्रेजुएशन करने तक कन्या उत्थान योजना के तहत एक बेटी पर कुल 54,100 रुपये अनुदान दे रही है। इसके अलावा अन्य छात्रवृति योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। महिलाओं के विकास के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जब तक आधी आबादी सशक्त नहीं होगी, तब तक समाज मजबूत नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के जो छात्र, छात्राएं बी0पी0एस0सी0 की प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उन्हें 50,000 रुपए की राशि उपलब्ध करायी जाएगी ताकि सफलता के लिए वो आगे अच्छी तैयारी कर सकें। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के जो छात्र, छात्राएं यू0पी0एस0सी0 की प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उन्हें 1,00000 रुपए की राशि उपलब्ध करायी जाएगी ताकि सफलता के लिए वे आगे अच्छी तैयारी कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग गांधी जी, लोहिया जी, जे0पी0 जी के अनुयायी हैं, हर पल, हर क्षण राज्य के लोगों की चिंता करते हैं। जितनी सारी योजनाएं चलायी जा रही हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसका सर्वे कराकर जीविका समूह के माध्यम से मदद की जाएगी। हमलोग न्याय के साथ विकास करते रहेंगे। हर तबके का विकास, हर इलाके का

विकास किया जा रहा है। मगध की धरती को नमन करता हूं और स्व0 सुखदेव प्रसाद वर्मा जी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं।

मुख्यमंत्री ने सुगांव में एक पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री का स्वागत शिक्षा मंत्री श्रीकृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने पुष्प–गुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंटकर किया। जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत फुलों की बड़ी माला पहनाकर किया गया। मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने स्व0 सुखदेव प्रसाद वर्मा जी की जीवनी पर आधारित पत्रिका का भी विमोचन किया। कला जत्था के कलाकारों द्वारा गीत का प्रस्तुतीकरण किया गया।

सभा को बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा एवं विधि मंत्री श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, उद्योग मंत्री एवं जहानाबाद जिले के प्रभारी मंत्री श्री जय कुमार सिंह, सांसद श्री अरुण कुमार, विधान पार्षद श्री सी0पी0 सिन्हा, पूर्व मंत्री श्री अभिराम शर्मा ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर विधायक श्री विनोद प्रसाद यादव, विधायक श्री सत्यदेव सिंह कुशवाहा, विधायक श्री अशोक कुमार सिंह, विधायक श्री निरंजन मेहता, विधान पार्षद श्रीमती रीना यादव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, गांववासी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

******